

The Gazette of India

असाधारएा

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 503] No. 503] नई विल्ली, रविवार, नवस्वर 12, 1978/कार्तिक 21, 1900 NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 12, 1978/KARTIKA 21, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह में प्राप्तय

प्रधिसूचना

नई विस्ली, 12 नवम्बर, 1978

का॰ग्रा॰ 645(ग्र).—-राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्न-लिखित ग्रादेश सर्थसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:---

मावेश

यतः मुझे, नीलम संजीव रेड्डी, भारत के राष्ट्रपति की, पाण्डिचेरी संघ राश्त्र क्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है घीर उस रिपोर्ट पर विवार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उस्पन्न हो गई है जिसमें पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र गासन भाधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रशिविषयम" कहा गया है) के उपबंधों के धनुसार नहीं चलाया जा सकता;

चतः भव, भविनियम की घारा 51 द्वारा प्रवत्त शक्तियों भीर उस निनित नुप्ते सनर्थे बनाने वाली सभी भन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस भावेण द्वारा⊸-

 का प्रथम परन्तुक; भीर उपधारा (5) का उतना माण जो उपाध्यक्ष के वेतन ग्रीर भत्तों से संबंधित है;

धारा 8 से 12 (जिनमें बोनों घारा सम्मिलित हैं) घारा, 15 से 17 (जिनमें बोनों घारा सम्मिलित हैं), भौर धारा 22:

धारा 27 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व प्रनुमोदन की प्रावश्यकता होती है भौर उसी धारा की उपधारा (3) के खंड (ग) का उतना भाग जो उपाध्यक्ष के बेतन और भन्तों से संबंधित है;

धारा 30 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके किए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है;

भारा 33, घारा 34 की उपधारा (2) भीर धारा 36;

षारा 44 भौर 45;

मारा 46 की, उपधारा (1) भीर उपधारा (2) में, निम्निमिखित उपबंध, भ्रमीत्,

> "क्या अपने मंक्षिपों की सभाह पर मा अन्यवा विद्यागया"; स्रोर

प्रादा 50 का उक्तना भाग को मंद्रिमंक्स से संबंधित है; प्रोप

तिम्निधित झानुवैनिक धौर नारिकामिक धपश्रंत बचाता हूं
 जो मुझे पुर्वोक्त घनिक ने वौरान संनिवान के झमुष्केष 260

के अनुसार पाण्डिकेरी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन करने के लिए आवश्यक अौर समीचीन प्रतीत होते हैं, अर्थात्:---

- (1) उक्त संघ राज्य क्षेत्र की विधान संभा भंग की जासी है;
- (2) अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री उस हैसियत से अपने पद पर नहीं रहेंगे;
- (3) जब तक संवर्ध से झन्यथा भ्रषेकित न हो, उक्त संघ राज्यक्षील के संबंध में, अधिनियम की घारा 6, 23, 27, 28, 30 और 49 में प्रशासक के प्रति किसी निर्वेश का अर्थ राष्ट्रपति के प्रति निर्वेश लगाया जाएगा और धारा 23, 27 से 31 (जिनमें बोनों घारा सिम्मिक्तित है) 48 और 49 में किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा के प्रति किन्हीं शब्दों में निर्वेश का जहां तक उसका संबंध उसके क्रस्यों का और शक्तियों से है, अर्थ, संसद के प्रति निर्वेश लगाया जाएगा।

हस्ता ०/-नीलस संजीव रेड्डी भारत का राष्ट्रपति

नई विल्ली, 12 नवम्बर, 1978

[सं ॰ यू ॰-11012/9/78-यू ०टी ॰एल ०] म ॰ ला ॰ कम्पानी, धपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1978

S.O. 645 (E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, have received a report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and after considering the report, I am satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Union territory of Pondicherry cannot be carried on in accordance with the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), (hereinafter referred to as "the Act");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby—

(a) suspend, for a period of six months from the date of this order, in relation to the said Union territory of

Pondicherry, the operation of the following provision of the Act, namely:—

- sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 6:
- in section 7, sub-sections (1), (3) and (4), clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;
- sections 8 to 12 (both inclusive), sections 15 to 17 (both inclusive);

section 22;

- so much of sub-section (1) of section 27 as requires the previous approval of the President and so much of clause (c) of sub-section (3) of the same section as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;
- so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President;
- section 33, sub-section (2) of section 34 and section 36; sections 44 and 45;
- sub-section (1), and the following provision, namely, "whether taken on the advice of his Ministers or otherwise" in sub-section (2), of section 46; and
- so much of section 50 as relates to the Council of Ministers; and
- (b) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period, namely:—
 - (i) the Legislative Assembly of the said Union territory is hereby dissolved;
 - (ii) the Chief Minister and the other Ministers appointed under sub-section (1) of section 45 of the Act shall cease to hold office as such;
 - (iii) in relation to the said Union territory, unless the context otherwise requires, any reference in sections 6, 23, 27, 28, 30 and 49 of the Act to the Administrator shall be construed as a reference to the President and any reference in sections 23, 27 to 31 (both inclusive), 48 and 49 to the Legislative Assembly of a Union territory by whatever form of words shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed as a reference to Parliament.

Sd/-

NEELAM SANJIVA REDDY, President of India New Delhi,

the 12th November 1978.

[No. U-11012/9/78-UTL] M. L. KAMPANI, Addl. Secy.